विख्यात चित्रकार रैंम्ब्रैन्ट को अन्य समकालीन कलाकारों के विपरीत अपने जीवनकाल में ही असाधारण सफलता मिल गई थी। इस डच कलाकार की कलाकृतियाँ ना केवल नीदरलैंड्स में बल्कि पूरे यूरोप में विख्यात थीं। उसके शिष्य भी "डच गोल्डन एज" में काफी प्रभावशाली हुए। रैंम्ब्रैन्ट एक जानी मानी हस्ती थे, इसलिए 17 वीं सदी के इस कलाकार की अज्ञात एवं अतिदुर्लभ कृतियाँ मिलने से कला जगत में खलबली मच जाती है। क्रिस्टीज़ ऑक्शन हाउस में, पुराने महान कलाकारों के विशेषज्ञ, हैरी पैंटिफर को हाल ही में रैंम्ब्रैन्ट की दो कृतियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, ये पेंटिंग्स पूरी तरह से अज्ञात थीं और 19 वीं और 20 वीं सदी के, रैंम्ब्रैन्ट से सबंधित किसी भी साहित्य में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस पेंटिंग्स को संभवतया 200 साल पहले जनता ने देखा था। एक पेंटिंग में प्लम्बर, जैन विलैम्स वैन डर प्लोयम और दूसरी में उसकी पत्नी जापगेन कैरैल्स नज़र आ रहे हैं। यह युगल डच शहर लायडन में रहता था। उनका रैंम्ब्रैन्ट से आजीवन रिश्ता रहा। उनके बेटे की शादी रैंम्ब्रैन्ट की चचेरी बहन से हुई थी और समझा जाता है कि, इस शादी से जन्मे पुत्र ने रैंम्ब्रैन्ट से कला की ट्रेनिंग ली थी। ये लोग रैंम्ब्रैन्ट के बेहद करीबी थे। इस परिवार ने ही 1824 में ये कलाकृतियां एक ब्रिटिश परिवार को बेची थीं, जिनके पास आज भी ये मौजूद हैं। इस ब्रिटिश परिवार को पता नहीं था कि पेंटिंग्स के उनके संग्रह में ये दो दुर्लभ पेंटिंग भी हैं। सन् 1635 की हस्ताक्षरित ये दोनों दुर्लभ कलाकृतियां 8 इंच लम्बी और साढ़े 6 इंच चौड़ी हैं। पैंटिफर ने कहा, "मुझे लगता है कि रैंम्ब्रैन्ट द्वारा बनाए गए ये सबसे छोटे पोर्ट्रेट्स हैं।"

कांग्रेस को 250 के आसपास सीटें देना चाहता है संयुक्त विपक्ष?

चर्चाओं के अनुसार सीट शेयरिंग का बेसिक फॉर्मूला है कि, 2019 में जिस पार्टी ने जो सीट जीती, वो उसकी, तथा नंबर-2 पर रही पार्टी को प्राथमिकता देना इस फॉर्मूला का दूसरा स्टेज है

नई दिल्ली, 29 मई। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ प्लान 475 तैयार कर रहे हैं। इस प्लान की सबसे प्रमुख बात यह है कि, वे चाहते हैं कि, लोकसभा की 543 सीटों में से कम से कम 475 सीटों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष से सिर्फ एक कैंडिडेट लड़े। कैंडिडेट कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का लेकिन लड़े कोई एक जिससे वोट ना बंटे और बीजेपी को आमने-सामने की लड़ाई में हराकर 2024 में लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने से रोका जा सके।

■ नीतीश कुमार चाहते हैं कि, लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ 475 सीटों पर विपक्ष का केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़े।

सूत्र बताते हैं कि, 475 सीटों पर एक कैंडिडेट देने का वो फॉर्मूला जिस पर चर्चा होगी उसमें 2019 में जीती सीटों का सबसे अहम रोल है। बेसिक फॉर्मूला है कि 2019 में जिस पार्टी ने जो सीट जीती, वो उसकी। नंबर 2 पर रही पार्टी को प्राथमिकता देना फॉर्मूला का दूसरा स्टेज है। क्षेत्रीय दल इस फॉर्मूले पर कांग्रेस से सीट के बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। किसी सीट पर नंबर 1 और 2 पर रही पार्टी अगर विपक्षी खेमे में नहीं हो तो तीसरे नंबर पर रही पार्टी को तवज्जो दिया जाए। लब्बोलुआब यह है कि 2019 के चुनाव में विपक्षी खेमे की जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लाई, उसका उस सीट पर हक माना जाए।

दिक्कत ये है कि कांग्रेस ये फॉर्मूला मान लेती है तो उसे 2024 के चुनाव में 250 से कुछ ज्यादा या कम सीटें लड़ने के लिए मिल पाएंगी जहां वो जीती या कम से कम दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में विपक्षी गठबंधन जीत भी जाए तो सरकार चलाने और गिराने का बटन कोलकाता से चेन्नई तक बिखरा रहेगा। लेकिन कांग्रेस की एक मुसीबत यह भी है कि सीधी लड़ाई में भाजपा कांग्रेस पर बहुत भारी है। अब पूरी कवायद विपक्षी इस बात पर टिकी है कि, कांग्रेस करीब 250 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाये। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ इसी फॉर्मूले पर मंथन के लिए आगामी 12 जून को पटना में सभी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है।

2014 के लोकसभा चुनाव में 189 सीटों पर सीधी टक्कर में 166 बीजेपी जीती जबकि 2019 में 192 सीटों पर आमने-सामने के मुकाबला में 176 भाजपा जीती। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 52 सीट जीती और 209 पर दूसरे नंबर पर रही। 2014 के चुनाव में कांग्रेस 44 सीट जीती थी और 224 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। जीत और रनर अप मिला दें तो कांग्रेस 2014 में 268 सीट और 2019 में 261 सीट पर जीती या आगे रही।

ममता और नीतीश के फॉर्मूले से कांग्रेस को लगभग 250 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। बाकी सीटों पर यूपी में अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे क्षत्रप अपनी-अपनी पार्टी को महत्व, नेतृत्व और ज्यादा सीटें चाहते हैं। मतलब ये कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है वहां वो उस राज्य की ताकतवर पार्टी द्वारा दी गई सीटें लड़े।

कांग्रेस जिस हालत में है उसमें 2024 में भाजपा को हटाने के लिए वो क्षेत्रीय दलों से सीटों की सौदेबाजी में कितना झुक सकती है, अब सारा खेल इस पर टिकने वाला है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अगर ये भरोसा देने में कामयाब हो जाते हैं कि पहले नंबर जुटाना है और बाद में सबसे बड़ी पार्टी ही सरकार का नेतृत्व करेगी।

'दोनों नेताओं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर, इसके तौर तरीकों व प्रक्रिया का ब्यौरा तैयार करने का निर्णय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है।

राहुल गांधी आज रात अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या तुरंत कोई निर्णय लिया जा सकता है।

इसलिए कांग्रेस नेतृत्व तेजी से काम कर रहा है और पायलट को राज्य व्यापी आंदोलन करने से रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यह नेतृत्व के लिए भारी शर्मिंदगी का सबब साबित हो रहा है।

सचिन पायलट को अपना आंदोलन वापस लेने के लिए कारण बताने होंगे। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं को एक साथ रखा जाए और संभावना है कि गहलोत को मनमानी करने की छूट नहीं मिले।

12 जून को पटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था तथा घोषित कर दिया था कि वे अपने दम पर ही 2024 के चुनाव लड़ेंगे। कुमार "वन-टू-वन" के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुये हैं कि 2024 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के समय विपक्ष का एक ही प्रत्याशी खड़ा हो तथा वे इस विचार की भी वकालत और हिमायत कर रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के समान दूरी रखने की धारणा क्षेत्रीय दलों के लिये अपनी पराजय को आमंत्रित करने वाली सिद्ध होगी। सूत्रों का कहना है कि 18 विपक्षी दलों के नेता, जिनमें एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार, ओडिशा तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा ममता बनर्जी, राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पटना मीटिंग में उपस्थित होंगे।

विपक्षी एकता अभी दूर की कौड़ी बनी हुई है क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं के ग्रुप अपनी समान्तर गतिविधियाँ जारी रखे हुये हैं। ममता बनर्जी तथा अखिलेश यादव स्वतंत्र रूप से कांग्रेस रहित तीसरे मोर्चा के विचार को आगे बढ़ाने में लगे हुये हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चन्द्रशेखर राव सहित, विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि दिल्ली अध्यादेश का समर्थन रोका जा सके। लेकिन बिहार के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि "क्षेत्रीय दलों के अधिकांश नेता भाजपा सरकार के इशारे पर ई.डी./सी.बी.आई. केसों के साझा खतरे का सामना कर रहे हैं। इसलिये इन पार्टियाँ को किसी औपचारिक या अनौपचारिक गठबंधन में शामिल होने के लिये स्वत: ही बाध्य हो जायेंगी।

'अपवाद कानून नहीं हो सकता'

हाई कोर्ट ने गैर आर.ए.एस. को पदोन्नत कर आई.ए.एस. बनाने पर तीखी टिप्पणी की

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 29 मई। राजस्थान हाई कोर्ट में गैर आर.ए.एस. (राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) से सीधे "इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस" (आई.ए.एस.) अफसर के पद पर एक 'सब-कोटा' के माध्यम से पदोन्नत किए जाने की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस प्रथा के संबंध में जवाब मांगा है और पिछले पाँच वर्ष के ऑकडे भी माँगे है। एक्टिंग सी.जे.एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की याचिकाओं पर दिया।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि 'ऑल इंडिया सर्विस एक्ट' व उसके नियम-विनियम के तहत 66.67 प्रतिशत आई.ए.एस. अफसर 'यू.पी.एस.सी.' परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती किए जाते है। वहीं 33.33 प्रतिशत आई.ए.एस. पद राज्य के प्रशासनिक अफसरों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया कि अपवाद स्वरूप में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी आई.ए.एस. के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। परन्तु इन अफसरों की संख्या राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नित होने वाले अफसरों की कुल संख्या की केवल 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यह नियम एक अपवाद है और यह तरीका पदोन्नतित की नियमित प्रक्रिया नहीं हो सकती। तनवीर अहमद ने बताया कि राज्य सरकार ने इस अपवाद को प्रथा मान कर पिछले कई वर्षो से आर.ए.एस. अफसरों से पदोन्नत होकर आई.ए.एस. बनाए जाने वाले कुल अफसरों में से 15 प्रतिशत का कोटा गैर आर.ए.एस. अफसरों का बना दिया है, जिस पर निरंतर अमल किया जा रहा है। अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर ऐसी प्रथा अपनाई जा रही है तो यह नियम का साफ उल्लंघन होगा। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है। सुनवाई की अगली तारीख जुलाई में तय की गई है।

सी.बी.आई. ने ब्रिटिश एयरोस्पेस और रोल्स रॉयस कंपनी के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की

सी.बी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार 2003-2012 के बीच सेना के लिए 115 मॉर्डन हॉक विमानों की खरीद में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है

नई दिल्ली, 29 मई। भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए हॉक 115 मॉडर्न जेट ट्रेनिंग विमान की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप मामले में सी.बी.आई. ने अपना ऐक्शन तेज कर दिया है। जांच एजेंसी ने ब्रिटिश एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी रोल्स-रॉयस पी.एल.सी., इसकी इंडियन यूनिट के सीनियर अधिकारियों व शस्त्र विक्रेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है।

एफ.आई.आर. के अनुसार, सी.बी.आई. ने मामले में 6 साल की जांच पूरी होने के बाद आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत रोल्स-रॉयस इंडिया के निदेशक टिम जोन्स, हथियार आपूर्तिकर्ता सुधीर चौधरी और उनके बेटे भानु चौधरी व ब्रिटिश एयरोस्पेस सिस्टम्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी रोल्स रॉयस से इस पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

अधिकारियों ने बताया कि, 2017 में एक ब्रिटिश अदालत ने भी समझौते को अंजाम देने के लिए कंपनी की ओर से बिचौलिए को शामिल करने और कमीशन का भुगतान करने का जिक्र किया था। यह आरोप है कि 2003-12 के दौरान साजिश में शामिल इन आरोपियों ने 73.42 करोड़ ब्रिटिश पाउंड की लागत से 24 हॉक 115 एजेटी की खरीद का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। उन्होंने

■ यह आरोप है कि, 2003-12 के दौरान साजिश में शामिल इन आरोपियों ने 73.42 करोड़ ब्रिटिश पाउंड की लागत से 24 हॉक 115 एजेटी की खरीद का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

30.82 करोड़ अमेरिकी डॉलर और 75 लाख अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि के लिए रोल्स रॉयस को आपूर्ति की गई सामग्री के बदले हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के 42 अतिरिक्त विमानों के लाइसेंस निर्माण की अनुमति दी।

सी.बी.आई. की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि यह सौदा रोल्स रॉयस द्वारा बिचौलियों को दी गई भारी भरकम रिश्वत, कमीशन और भ्रष्टाचार के एवज में किया गया था, जबकि समझौते से संबंधित दस्तावेज में बिचौलियों के भुगतान पर रोक की बात कही गई थी। एचएएल ने अगस्त 2008 से मई 2012 के बीच भारतीय वायु सेना को 42 विमान दिए। जनवरी 2008 में एचएएल ने रक्षा मंत्रालय से 9,502 करोड़ रुपये की लागत से 57 अतिरिक्त हॉक विमान के निर्माण के लिए लाइसेंस देने की अपील की थी, जिसमें से 40 विमान वायु सेना के लिए और 17 नौसेना के लिए था।

सी.बी.आई. जांच से पता चला है कि, 2006-07 में आयकर विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान रोल्स रॉयस इंडिया कार्यालय से लेन-देन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे, लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने जांच से बचने के लिए दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और हटा दिया।

मणिपुर में हिंसा और तेज हुई

हथियारबंद आतंकियों ने गाँवों में आम लोगों के घरों पर हमला किया, सुरक्षाबलों ने 25 हथियारबंद आतंकियों को गिरफ्तार किया है

इम्फाल, 29 मई (वार्ता)। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार को लीमाखोंग सैन्य मुख्यालय के पास खुरखुल एवं अन्य मैतेई गांवों में हथियारबंद आतंकियों ने हमला किया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने के कारण ग्रामीण आसपास के स्थानों की ओर भाग गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात राज्य पहुंचने वाले हैं जिसके लिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

सैनिकों ने हथियार रखने एवं घरों को जलाने की कोशिश करने के आरोप में 25 लोगों को भी गिरफ्तार किया। राज्य के सभी पांच जिलों में पूरे दिन कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई और 3 मई से झड़पें शुरू होने के बाद से वहां इंटरनैट भी बंद है।

मुख्यमंत्री एन बीरेन ने कहा कि यह संघर्ष अब सशस्त्र कुकी आतंकियों और सरकार के बीच है। इंफाल पूर्व जिले में इंसास राइफल और मैगजीन के साथ तीन लोगों को 5.56 एमएम की 60 गोली, गोला-बारूद, एक चीनी हथगोला और एक डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया गया।

एक अन्य घटना में सेना ने इंफाल पूर्व में घरों को जलाने की कोशिश करने वाले 22 लोगों को गिरफ्तार किया, उन आतंकियों ने स्वचालित हथियारों से सेना की टुकड़ियों पर गोलियां भी चलाईं। उनके पास से पांच 12 बोर की डबल बैरल राइफल, तीन सिंगल बैरल राइफल, डबल बोर वाला एक देसी कट्टा और एक मज़ल लोडेड हथियार भी बरामद किया गया। सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों के बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित किया और आगजनी की अनेक घटनाओं को रोका।

इस बीच, मणिपुर के मुख्य सचिव डॉ. विनीत जोशी ने एक आदेश में कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए कई लोग मणिपुर के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर रहे हैं लेकिन उनमें से कई सूचनाएं गलत, फर्जी और झूठी अफवाह पाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी गलत सूचनाएं जनता को गुमराह करती है, हिंसा भड़कती है और हथियारों का उपयोग करने और राज्य के खिलाफ विद्रोह करके राज्य में वर्तमान स्थिति को खराब करने की क्षमता रखती है, जिससे मानवीय जीवन को नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है और संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है।

पेपर लीक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार ने ये आदेश दिए हैं।

शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की थी। इस बैठक में अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को भी प्रमोट किया गया था। अचंभे की बात है कि, शिक्षा विभाग ने बर्खास्त हो चुके शेर सिंह मीणा को प्रमोट कर दिया। इतना ही नहीं उसका पदस्थापन भी कर दिया गया।

निदेशक गौरव अग्रवाल ने शाम होते-होते इस आदेश को वापस ले लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सोमवार सुबह गौरव अग्रवाल को ही पद से हटा दिया। शिक्षा विभाग में पदोन्नति करने से पहले सभी कार्मिकों का रिकॉर्ड देखा जाता है। प्रत्येक कार्मिक के रिकॉर्ड की जांच की जाती है। आपत्ति भी मांगी जाती है।

डी.पी.सी. होने के बाद भी करीब एक महीने का वक्त रहता है। लेकिन, इसके बाद भी किसी के ध्यान में नहीं आया कि सेवा से बर्खास्त हो चुके कार्मिक को कैसे पदोन्नति दी गई।

जब यह खबर प्रमुखता से चली कि, एक करोड़ रुपये में सीनियर टीचर भर्ती का पेपर बेचने वाले मास्टरमाइंड अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को शिक्षा निदेशालय ने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन कर दिया तो शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने रात में नया आदेश जारी किया।

एर्दोगन फिर से तुर्किये के राष्ट्रपति चुने गये

नयी दिल्ली, 29 मई (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को फिर से चुनाव जीतने पर बधाई दी और कहा कि उन्हें विश्वास है कि द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ता रहेगा।

मोदी ने ट्वीट किया, तुर्किये के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर आर टी एर्दोगन को बधाई! मुझे विश्वास है कि आगामी समय में वैश्विक मुद्दों पर हमारे द्विपक्षीय संबंध और सहयोग बढ़ते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन चुनाव जीतकर फिर से पांच साल के लिए सत्ता में आए। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने रविवार को रन-ऑफ में करीब पूरी गिनती में 52.16 प्रतिशत मत हासिल किए। उन्होंने कहा कि अपनी जीत के साथ, एर्दोगन ने अपने शासन को तीसरे दशक तक बढ़ा दिया।

दरगाह में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुपरविजन में सलूम्बर थानाधिकारी लीलधर मालवीय के नेतृत्व में गठित दल ने इस मामले में आरोपी गोविन्द पुत्र बालाजी, ललित पुत्र पेमाराम, कैलाश पुत्र नाथुलाल, दयाराम पुत्र शंकरलाल, मांगीलाल पुत्र हिराजी, वीराराम पुत्र मावाराम निवासीयान पातुखेडा, कुराबड जिला उदयपुर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया।

'महिला चिकित्सक... न संसद की पुरानी बिल्डिंग रही... तीन राज्यों के ...

'महिला चिकित्सक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की हकदार थी।

उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी पाठ्यक्रम शुरु होने के पहले, एक तय तिथि के उपरांत नए "एडमिशन" नहीं दिये जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, केवल "रैअरेस्ट ऑफ रेर", यानी बिल्कुल ही अनूठी स्थितियों में ही इस नियम को तोड़ा जाना चाहिये। हाई कोर्ट ने उक्त मामले को "रेअरैस्ट ऑफ रेअर" माना है और अपीलार्थी को अगले सत्र में प्रवेश दिया है।

अपील में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि, अपीलार्थी वर्ष 2015 में डैंटल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई थी। साल 2018 में उसे अलवर की मंडावर कम्युनिटी हैल्थ सैंटर (सी.एच.सी.) में नियुक्त किया गया। इसके बाद करोना काल में उसे अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति दी गई। जहां उसने कुल 750 दिन तक काम किया। अपील में कहा गया कि, गत वर्ष की नीट पीजी परीक्षा में उसे नियमानुसार बीस बोनस अंक दिए जाने थे, लेकिन उसे इसका लाभ नहीं दिया गया। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार व अन्य की ओर से कहा गया कि, अपीलार्थी की मूल नियुक्ति शहरी क्षेत्र में थी और उसे कार्य व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लगाया गया था। जहां उसे ग्रामीण भत्ता भी नहीं दिया गया था। ऐसे में उसकी ओर से दी गई सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के तौर पर नहीं गिना जा सकता। इसी आधार पर एकलपीठ ने भी पूर्व में उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने माना कि, अपीलार्थी को बिना किसी गलती के पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से वंचित किया गया है। ऐसे में उसे अगले सत्र के पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए।

न संसद की पुरानी बिल्डिंग रही...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने का सबसे बेहतरीन जरिया है।

"लीक्स" और प्रैस तथा सत्ता के बीच मेलजोल के उस खत्म हो चुके दौर की घटना मुझे याद आती है जब एक ताकतवर प्रधानमंत्री अपने चयनित किन्तु अयोग्य व अकुशल प्रत्याशी को विशालकाय पब्लिक सैक्टर एयरलाइन ऑपरेटर का चेयरमैन नहीं बना सका था और न्यूज़ लीक होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था।

संसद की कार्यवाहियों में पत्रकारों को आने की अनुमति देने एक बार जब उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। तब सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने उन्हें इस कदर परेशान किया कि वे रुंआसे से हो गए थे। यह कार्यवाही टी.वी. पर नहीं आई थी। पर पत्रकारों ने यह खबर प्रकाशित की और सत्तारूढ़ पार्टी के उन उद्दण्ड सांसदों को शर्मिंदा होना पड़ा।

वह घटना भी याद है जब प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनकी कार्यशैली को लेकर जोरदार हमला बोला, उनकी घोर आलोचना की। डॉ. सिंह राजनेता तो है नहीं, तो वह यह सब सह नहीं पाए, उन्होंने तमाम आरोपों और आलोचना को बेहद गंभीरता और व्यक्तिगत स्तर पर ले लिया।

जब हालात और भी बुरा रूप ले रहे थे तब उनकी मदद को आगे आए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में डॉ. सिंह का बचाव किया।

अनुभवी राजनेता वाजपेयी ने डॉ. सिंह को सलाह दी कि अपनी "चमड़ी थोड़ी मोटी" कर ले और किसी भी बात को निजी तौर पर न लें। उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें याद है उन्हें उनके राजनैतिक करियर में काफी भला बुरा कहा गया। वैसे वाजपेयी हमारी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन राजनेताओं में से एक रहे हैं। यू.एन. में और संसद में उनके भाषणों को आज भी याद किया जाता है।

जब उनकी तेरह दिन की सरकार गिरी थी तब उनका भाषण निस्संदेह बहुत शानदार था। पर एक ऐसा मौका था जब संसद में अपने भाषण में उन्होंने राजनीतिक आकाश की ऊंचाइयां छू ली थीं।

उस समय आंध्र प्रदेश के कुछ विधायक दिल्ली आए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ज्ञापन देने। उनमें से एक या दो को प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए अंदर आने की अनुमति देने की बजाय दिल्ली पुलिस ने उन पर कार्यवाही की तब संसद चल रही थी और खबर अंदर पहुंची।

और तब वाजपेयी सदन में खड़े हुए और अपनी शानदार हिंदी में भाषण दिया।

प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे पर उन्होंने अपना भाषण प्रधानमंत्री को ही संबोधित किया। उन्होंने कहा, "अभी तक राज्यों के लोग दिल्ली में न्याय के लिए आते है, पर अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली को अपनी सत्ता बचाने के लिए राज्यों पर दस्तक देनी पड़ेगी।"

यह मानो एक संत की भविष्यवाणी थी और आने वाले वर्षों में केन्द्र को अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर होना पड़ा। निश्चित रूप से अब वो दौर खत्म हो गया है।

ऐसे दिन आते रहते हैं जब कर्मों का हिसाब होता पर अकलमंद लोग उसके अनुसार समझदारी से काम करते है।

तीन राज्यों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विकसित करने के लिये अत्यल्य समय ही मिल सके।

भाजपा नेताओं, खासतौर से मोदी-शाह की जोड़ी, के इस विचार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल का समर्थन भी प्राप्त है। इस जोड़ी का मानना है कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं के बीच बहुत गहरे अन्तर्विरोध हैं तथा उनमें तालमेल बनाने के लिये काफी समय और धैर्य की जरूरत होगी।

इसलिये भाजपा का मानना है कि समय पूर्व चुनाव कराना चुनावी लड़ाई में अपना पलड़ा भारी रखने के लिये बेहतर रणनीति सिद्ध होगी।

भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि, आम चुनावों को जल्दी तथा तीन हिन्दी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ कराने का एक और लाभ भी मिलेगा-कांग्रेस राज्य के चुनावों पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं कर पायेगी क्योंकि उसे राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देना होगा, इस प्रकार कांग्रेस संसाधनों के मामले में भी और ज्यादा असुविधा में रहेगी। भाजपा का मानना है कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी के पास संसाधनों का अकाल होगा, क्योंकि इसकी जमापूंजी खींचतान का शिकार हो जायेगी।

आम चुनाव जल्दी करवाकर, सत्तारूढ़ पार्टी यह सुनिश्चित कर लेगी कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा प्रस्तावित हिस्सा, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी का पूर्व से पश्चिम-हिन्दी भाषी क्षेत्रों से गुजरते हुये, तक जाना प्रस्तावित है, भी बाधित हो जायेगा। भारत जोड़ो यात्रा के पहले हिस्से के फलस्वरूप, कांग्रेस तथा राहुल गांधी-दोनों की ही विश्वसनीयता को आशातीत लाभ हुआ था, यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल यात्रा के दूसरे हिस्से के आयोजन की स्थिति ही आने देना नहीं चाहता।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908